



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण 1935 (श0)  
(सं0 पटना 893) पटना, मंगलवार, 10 दिसम्बर 2013

सहकारिता विभाग

अधिसूचना  
18 सितम्बर 2013

सं0 1/रा.स्था.(2)न्या.-05/11 सह.-3900—विभागीय अधिसूचना संख्या 2067 दिनांक 20.06.07 द्वारा श्री मौलेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लि., पटना को सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 6846/2003 मौलेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2004 के अनुपालन में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660वि.(2) दिनांक 08.02.99 की कंडिका-12 के तहत बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग) के प्रोन्नति सोपान के चिह्नित आवश्यकता आधारित पद के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 1920 दिनांक 13.07.02 के अनुक्रम में दिनांक 01.08.02 के प्रभाव से संयुक्त निबंधक, स.स. का वेतनमान रू. 12,000-16,500 स्वीकृत किया गया था।

दिनांक 15.11.2000 से उत्तरवर्ती बिहार के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 1011 दिनांक 13.04.2006 के द्वारा चिह्नित पद 01.01.96 को वेतनमान स्वीकृति तथा तत्पश्चात् प्रोन्नति प्रक्रिया पर वित्त विभाग का परामर्श, आरक्षण नीति लागू करने पर वित्त विभाग का परिपत्र संख्या 4388 वि.(2) दिनांक 10.06.2002 द्वारा दिये गये दिशानिर्देश तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से रोस्टर बिंदु विलयरेण पर परामर्श के साथ संयुक्त निबंधक, स.स. की पद उपलब्धता, वरीयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-58 के तहत उच्चतर कोटि के पद का प्रभार ग्रहण तथा विभागीय ज्ञापांक 229 दिनांक 10.02.2010 के द्वारा पारित तथ्यात्मक आदेश के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या 2067 दिनांक 20.06.07 के द्वारा श्री मौलेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लि., पटना को 01.08.02 से स्वीकृत संयुक्त निबंधक, स.स. का वेतनमान रू. 12,000-16,500 को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1389 दिनांक 30.03.10 द्वारा रद्द किया गया तथा श्री प्रसाद को भुगतान की जा चुकी अधिक राशि का समायोजन/वसूली उन्हें देय वेतनादि से कर लेने का भी आदेश दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध श्री मौलेश्वर प्रसाद द्वारा एक समादेश याचिका संख्या 7022/2010 दायर किया गया। उक्त समादेश याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22.09.2011 को पारित न्यायादेश— "...Even if the benefit was granted on the principle of parity under Article 14 of the Constitution, once the petitioner had reached his destination, he stands on his own strength. Before depriving him of the benefit his individual claim and rights have to be considered. The question of parity with another loses it relevance.

The petitioner has specifically asserted violation of the principles of natural justice. The impugned order does not display any consideration that notice was issued to the petitioner before passing an order adverse to him visiting him with civil consequences. That vitiates the order without further more. Once a Govt. servant retires, the master and servant relationship stands severed, issues of fraud being a class apart, the only control of the respondents over a superannuated employee is under the Bihar Pension Rules.

The impugned order dated 30.03.2010 passed on basis that a master and servant relationship after superannuation still subsists and in violation of the principles of natural justice is accordingly set aside..." है।

उक्त न्यायादेश के अनुपालन के आलोक में वित्त विभाग के परामर्शानुसार श्री मौलेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी तंबाकू उत्पादक संघ लि., पटना के लिए संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ वेतनमान रु. 12,000—16,500 में दिनांक 01.08.2002 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 29.02.2008 तक एक अधिसंख्य पद सृजन करने की कार्रवाई की गयी। प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा दिनांक 28.06.2013 की बैठक में उक्त अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति दी गयी। तत्पश्चात उक्त अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति एवं सृजित पद के विरुद्ध प्रोन्नति देने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 10.09.2013 के मद संख्या—11 द्वारा स्वीकृति दी गयी है। उक्त आलोक में विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक 272 दिनांक 17.09.13 द्वारा अधिसंख्य पद सृजन संबंधी राज्यादेश निर्गत है।

उपर्युक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1389 दिनांक 30.03.2010 को रद्द करते हुए श्री मौलेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लि., पटना को दिनांक 01.08.2002 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 29.02.2008 तक उक्त सृजित अधिसंख्य पद के विरुद्ध संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, वेतनमान रु. 12,000—16,500 में प्रोन्नति दी जाती है।

श्री प्रसाद के लिए संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ का वेतनमान रु. 12,000—16,500 में दिनांक 01.08.2002 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 29.02.2008 तक एक अधिसंख्य पद सृजन के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
मधुरानी ठाकुर,  
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 893-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>